

Need to provide subsidy to cooperative societies working in agriculture sector in Jalgaon District, Maharashtra

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए कार्यकारी सहकारी सोसाइटी (विविध कार्यकारी सोसाइटी) एक अहम भूमिका में मेरे महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वित है। मेरे जलगांव जिले में 900 से अधिक सोसाइटी कार्यान्वित हैं, जिसमें से 550 से अधिक सोसाइटी के हाल ही में हुए ऑडिट के अनुसार कई अलग-अलग कार्यकारी समितियों में प्रतिकूल असमानताएं (अवांछनीय अंतर) हैं। यह बहुत गंभीर और चिंताजनक मामला है। विकास सोसाइटियों के इस अवांछनीय अंतर में पड़ने का मुख्य कारण समिति के सभी सदस्यों से 100% फसली ऋण की वसूली न होना है। इसके कारण यह राशि हर साल बढ़ती जाती है और साथ ही सूखा, भारी बारिश और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान फसल ऋण का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं और ब्याज की बढ़ती राशि के कारण किसान सोसाइटी में ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं और अंततः ये विकास सोसाइटियां अनेक समस्याओं का सामना कर रही हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन सभी विकास सहकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराये जिससे ये सभी संस्थानों को निरंतर सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हों।

माननीय सभापति: श्री राजीव प्रताप रूडी जी ? उपस्थित नहीं।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल जी ? उपस्थित नहीं।

डॉ. सुजय विखे पाटील जी ? उपस्थित नहीं।

श्री मितेश पटेल जी ? उपस्थित नहीं।

डॉ. निशिकांत दुबे जी।

